झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

6572 - 20/10/17

संकल्प

विषय :- अमृत योजनान्तर्गत प्रस्तावित जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए स्वीकृत Model Bid Document में आंशिक संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

1. राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 28.12.2016 को संपन्न बैठक में मद सं॰ 13 के रूप में चास जलापूर्ति योजना (15623.37 लाख रुपये) को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. योजना के क्रियान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद् द्वारा अमृत योजनान्तर्गत स्वीकृत गिरिडीह जलापूर्ति परियोजना हेतु तैयार किए गए निविदा दस्तावेज को अमृत योजना अन्तर्गत सभी प्रस्तावित जलापूर्ति परियोजनाओं हेतु Model Bid Document के रूप में उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. चास नगर निगम द्वारा तकनीकी रूप से दक्ष कर्मियों के अभाव के कारण परियोजना का क्रियान्वयन जुडको लि॰ के द्वारा किए जाने का लिखित अनुरोध समर्पित किया गया है अतः योजना का क्रियान्वयन जुडको लि॰ द्वारा किया जाना है।

4. उपर्युक्त के आलोक में जुडको लि॰ द्वारा चास जलापूर्ति परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का चयन करने के निमित्त खुली निविदा प्रकाशित की गई थी। Pre-Bid Meeting की परिचर्चा के दौरान विभिन्न संस्थानों द्वारा Model Bid Document की कतिपय शर्तों को परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया।

5. जुडको लि॰ द्वारा निविदा की शर्तों में बिना कोई परिवर्तन किए निविदाऐं आमंत्रित की गई परन्तु एक ही निविदा (Single Bid) प्राप्त होने के कारण निविदा निरस्त करनी पड़ी।

6. पुनः आमंत्रित निविदा (2nd Call) के विरुद्ध दो निविदादाताओं द्वारा निविदाऐं समर्पित की गई परन्तु तकनीकी मूल्यांकन के उपरांत एक ही निविदादाता को तकनीकी योग्य पाया गया। अतः निविदा निरस्त करनी पड़ी।

7. तीसरी बार प्रकाशित (3rd Call) की गई निविदा के विरुद्ध भी एक निविदा प्राप्त हुई। तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय निविदा खोली गई परन्तु लागत से 32% अधिक मूल्य उद्धृत करने के कारण इस बार भी निविदा संपादित कर कार्य आवंटन नहीं किया जा सका।

8. निविदा के तीन बार असफल होने एवं अपेक्षा के अनुरूप निविदाऐं प्राप्त नहीं होने के कारणों की समीक्षा हेतु जुडको लि॰ के स्तर से दिनांक 23.05.2017 को निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण की अध्यक्षता में एक Bidders Meet का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया।

9. संस्थानों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि निविदा में उल्लेखित शर्तों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। संस्थानों के द्वारा यह भी सूचित किया गया कि अन्य राज्यों द्वारा भी अमृत योजनान्तर्गत प्रस्तावित जलापूर्ति परियोजनाओं के निविदा दस्तावेज भी इसी आधार पर तैयार किए गए हैं। संभावित निविदादाताओं ने यह आश्वस्त किया कि वांछित संशोधनोपरांत अपेक्षित मात्रा में निविदाऐं प्राप्त हो सकेंगी, जिसके आधार पर संस्था का चयन किया जायेगा।

10. प्राप्त निदेश के आलोक में जुडको लि॰ के द्वारा अन्य राज्यों में अमृत योजनान्तर्गत प्रस्तावित जलापूर्ति परियोजनाओं के निविदा दस्तावेजों का अध्ययन किया गया एवं तुलनात्मक विवरणी तैयार की गई।

11. तुलनात्मक विवरणी के अध्ययन एवं संभावित निविदादाताओं के सुझावों के आधार पर यह निष्कर्ष पाया गया कि अन्य राज्यों की निविदा दस्तावेज में निविदादाताओं के सुझाव पूर्व से ही सन्निहित हैं, जिसके कारण उन राज्यों की निविदाऐं सफल हो सकीं एवं कार्य प्रारंभ हो गया है।

12. कार्यहित को ध्यान में रखते हुए पूर्व में स्वीकृत Model Bid Document की विभिन्न शर्तों में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किए गए जो Annexure-1 के रूप में संलग्न है।

13. उपर्युक्त के क्रम में निम्नलिखित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क) कंडिका 1–11 में उल्लेखित प्रसंग के आधार पर कंडिका–12 में उल्लेखित Model Bid Document के प्रस्तावित संशोधन पर स्वीकृति।

ख) संशोधित निविदा दस्तावेज को अमृत योजनान्तर्गत प्रस्तावित सभी जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए Model Bid Document के रूप में उपयोग की स्वीकृति।

14. उपर्युक्त प्रस्तावों को राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 17.10.2017 को संपन्न बैठक में मद संख्या 5 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

20.10.17

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/MBD-Revision/106/2017 6572 (अ०उ०) राँची, दिनांक– 20/10/17

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.10.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/MBD-Revision/106/2017 6572 (अ०उ०) राँची, दिनांक– 20/10/17

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/विशेष सचिव, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर (हजारीबाग), दक्षिणी छोटानागपुर (राँची), कोल्हान (चाईबासा), संथाल परगना (दुमका)/उपायुक्त, राँची, धनबाद, बोकारो, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह एवं सराईकेला–खरसावाँ/सभी अमृत शहरों के नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी/जुडको लि०/श्री कुणाल कुमार, विभागीय वेब मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित।

20.10.17

सरकार के प्रधान सचिव।

Ref. Clause	Provision as per existing SBD	Provision as per other state SBD (Under AMRUT/JNNURM scheme)	Provision as requested by Bidder during Bidders Conference	Proposal
SECTION 2 Information To Bidders (ITB) **4.5 A (B)**	The contractor/firm must have satisfactorily completed (of work whose experience certificate is submitted) as a prime contractor at least one similar work of value not less than amount indicated in Appendix (usually not less than 50% of estimated value of contract of last five years) i.e. 0.5 X..... lakh= Rs ....Lakhs) Similar works means any water supply project which consist of minimum two components such as Construction of ESR and supplying laying and Jointing DI K7 Pipe lines.		Contractor has requested for inclusion of DI/CI/HDPE pipes in place of DI K7 pipe only.	The contractor/firm must have satisfactorily completed (of work whose experience certificate is submitted) as a prime contractor at least one similar work of value not less than amount indicated in Appendix (usually not less than 50% of estimated value of contract of **last seven years**) i.e. 0.5 X..... lakh= Rs ....Lakhs) Similar works means any Water supply project which consist of minimum two components such as construction of ESR, WTP, supplying, **laying and jointing of DI/CI/MS/HDPE** pipelines.
SECTION 2 Information To Bidders (ITB) 4.5 A (c) SECTION 2 Information To Bidders (ITB) 4.5 A (c) of ITB	Executed in any one year in last five years, the minimum quantities of the following items of work as indicated in Appendix. - RCC Intake Well (25%) - WTP(50 %) - ESR(50 %)	**MADHYA PRADESH** Financial Experience of having successfully executed, a) three similar works each costing not less than the amount equal to 20% of the probable amount of contract during the last 5 financial years; or b) two similar works each costing not less	Few Service Provider constructed higher capacity structure, for which construction period required more than a year. Therefore, requested to delete one year criteria.	Executed in last Seven Financial years, the minimum quantities of the following items of work as indicated in Appendix. - RCC Intake Well (25%) - WTP (50%) - ESR (50 %)

Ref. Clause	Provision as per existing SBD	Provision as per other state SBD (Under AMRUT/JNNURM scheme)	Provision as requested by Bidder during Bidders Conference	Proposal
	- Pipeline (25 % of total length) - Motor Pump (VT)(50%) - Transformer (50 %)	than the amount equal to 30% of the probable amount of contract during the last 5 financial years; or c) one similar work of aggregate cost not less than the amount equal to 50% of the probable amount of during the last 5 financial years; **ODISHA** The Firms/ Companies/ Registered Contractors should have successfully Completed & Commissioned Works of similar type valuing not less thanRs.638.86 Lakh (30% of the estimated cost) in any one year during the last 5(five) years. However, such similar type of work must cover at least one Conventional Water Treatment Plant or Intake Well or Elevated Service Reservoir or Ground Storage Reservoir of any capacity or laying of pipeline works or RCC Chimney/Silos. The firm shall have to submit the performance certificate of the works constructed by them for satisfactory performance from appropriate authority i.e., not below the rank of Executive Engineer/ equivalent. Weightage @ 10% per year shall be given on the value of the completed work in the preceding years.		- Pipeline (25 % of total length) - Motor Pump (VT) (50%) - Transformer (50 %) The bidder should have executed laying and jointing (25% of total length) length of diameter 100mm to 900mm DI, CI, MS, HDPE pipe and Bidder should have experience in any of the following: • SCADA project including Bulk AMR (Automatic Meter Reading). • Level transmitters and Maintenance in water supply projects

Ref. Clause	Provision as per existing SBD	Provision as per other state SBD (Under AMRUT/JNNURM scheme)	Provision as requested by Bidder during Bidders Conference	Proposal
		DELHI JAL BOARD Mandatory Technical Capacity: The Bidder shall, either by itself or through its Associate, meet the following mandatory technical experience criteria in Water Sector ("Mandatory Technical Capacity"). In case of a Consortium, the Bidder shall include a Member, who, either by itself or through its Associate, shall mandatorily meet the following technical experience criteria in Water Sector: (b) Experience in execution of capital works in water transmission and distribution as under: i. At least One project reference of minimum amount of Rs 138 crore (Rs. One Hundred and Thirty-Eight Crore) in single order; or, ii. At least Two project references of minimum amount of Rs 86 crore (Rs. Eighty-Six Crore) each. iii. At least Three project references of minimum amount of Rs 69 crore (Rs. Sixty-Nine Crore) each.		
SECTION 5 (Technical Specification) 5.1.3	5.1.3 Time for Completion Time of completion of above mentioned scope of works shall be 24 months (inclusive of monsoon period & from the date of issue		Service Provider / Bidder requested for minimum 36 months for the completion of the project.	5.1.4 Time for Completion Time of completion of above mentioned scope of works shall be 36 months for the **project cost having more than**

Ref. Clause	Provision as per existing SBD	Provision as per other state SBD (Under AMRUT/JNNURM scheme)	Provision as requested by Bidder during Bidders Conference	Proposal
	of work order. Trial Run period will be for 3 months after successful completion & commissioning of the works as certified by the Engineer In Charge followed by five years of operation and maintenance (O & M) which includes first two years as defect liability period.			**100 crores** (inclusive of monsoon period) & from the date of issue of work order. Trial Run period will be for 3 months after successful completion & commissioning of the works as certified by the Engineer In Charge followed by five years of operation and maintenance (O & M) which includes first two years as defect liability period.
Operation and Maintenance for 5 years FOURTH SCHEDULE 1.2	The payment of the Fixed O&M Fee and the Variable O&M Fee shall commence from the start of the operations and maintenance period. The payments collectively here in after are referred to as "Contractor Fee"		Requested to include O & M fees during construction period (as because several DMA will be implemented during EPC period / construction period)	O & M fees incorporated during construction period as per planned schedule 5.1.5 Key Performance Indicators (KPI) of O&M activities has been revised